शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 8पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 16 – 23 फरवरी 2026 मूल्य पांच रूपये

विधानसभा में राजस्व घाटा अनुदान और कर्ज के आंकड़ों पर सत्ता-विपक्ष आमने सामने

शिमला/शैल। सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजस्व घाटा अनुदान (आर.डी.जी), वित्त आयोगों की सिफारिशों, टैक्स डेवोल्यूशन और ऋण प्रबंधन को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। दोनों पक्षों ने अपने-अपने कार्यकाल के आंकड़े रखते हुए एक-दूसरे पर भेदभाव, वित्तीय कुप्रबंधन और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाये।

विपक्ष की ओर से सदन में बोलते हुए सदस्यों ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान का इतिहास बताता है कि समय-समय पर हिमाचल प्रदेश को केंद्र से पर्याप्त सहयोग मिला है। उन्होंने छठे वित्त आयोग (1974) से लेकर 13वें वित्त आयोग तक के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रत्येक आयोग में अनुदान राशि में वृद्धि हुई। उनके अनुसार छठे वित्त आयोग में 161 करोड़ रुपये, सातवें में 207 करोड़ रुपये, आठवें में 223 करोड़ रुपये, नौवें में 523 करोड़ रुपये, दसवें में 772 करोड़ रुपये, 11वें में 1,979 करोड़ रुपये, 12वें में 10,202 करोड़ रुपये तथा 13वें में 7,879 करोड़ रुपये हिमाचल को प्राप्त हुए।

विपक्ष का तर्क था कि वर्ष 2010 से 2014-15 के बीच अनुदान राशि में कमी आई, जबकि उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। उनका कहना था कि लंबे समय तक केंद्र में कांग्रेस सरकारों के दौरान कुल मिलाकर लगभग 20,956 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि 14वें वित्त आयोग के दौरान केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को 40,624 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। 15वें वित्त आयोग में 11,431 करोड़ रुपये तथा कुल मिलाकर लगभग 37,189 करोड़ रुपये मिलने का दावा किया गया। विपक्षी सदस्यों के अनुसार पिछले 12 वर्षों में लगभग 89,254 करोड़ रुपये हिमाचल को दिये गये, जो पूर्ववर्ती 40 वर्षों की तुलना में साढ़े चार गुना अधिक है। ऐसे में प्रदेश के साथ भेदभाव का आरोप तथ्यात्मक नहीं है।

प्रकाश राणा ने ऊर्जा क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 100 मेगावाट के एक प्रोजेक्ट से प्रतिदिन 75 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का राजस्व संभावित है। उन्होंने प्रश्न किया कि 14 हजार मेगावाट की परियोजनाएं प्रदेश से बाहर क्यों चली गई। उनका दावा था कि यदि 14,000 मेगावाट की क्षमता का पूर्ण दोहन होता तो वार्षिक स्तर पर लगभग 50,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व संभव था। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध प्रदेश को कर्ज पर निर्भर रहने की बजाय अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना चाहिए।

बिक्रम सिंह ने टैक्स डेवोल्यूशन का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र से मिलने वाले हिस्से में 83 प्रतिशत से बढ़कर 91.4 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। वर्ष 2026 में लगभग 13,950 करोड़ रुपये का हिस्सा मिलने की बात कही गई, जो पिछले वर्ष से 2,450 करोड़ रुपये अधिक बताया गया। ग्रामीण और शहरी विकास मद में 4,179 करोड़ रुपये तथा एसडीआरएफ और डीएमएफ मद में 2,682 करोड़ रुपये मिलने का उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग में जहां 40,624 करोड़ रुपये मिले, वहीं 15वें वित्त आयोग में यह राशि लगभग 48,000 करोड़ रुपये के करीब रही। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, नाबार्ड, विश्व बैंक, रेलवे, सुरंग और फोर-लेन परियोजनाओं को मिलाकर कुल सहायता लगभग 2.12 लाख करोड़ रुपये के आसपास होने का दावा किया गया।

विपक्ष ने कर्मचारियों के 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया, एचआरटीसी पेंशन के भुगतान में देरी और मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ न मिलने जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उनका प्रश्न था कि यदि 31 मार्च तक वित्तीय स्थिति सामान्य थी, तो तीन वर्षों में लंबित देनदारियों का समाधान क्यों नहीं किया गया। साथ ही 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के दावों पर भी सवाल उठाए गए।

बहस के दौरान यह भी कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 12वें और 13वें वित्त आयोग के दौरान लगभग 18,000 करोड़ रुपये आर.डी.जी. के रूप में मिले, जबकि बाद में एनडीए सरकार के दौरान 14वें और 15वें वित्त आयोग में लगभग 78,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। विपक्ष ने इसे 60,000 करोड़ रुपये का अंतर बताते हुए वर्तमान सरकार पर तथ्यों की अनदेखी का आरोप लगाया।

प्राकृतिक आपदाओं का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में बाढ़ और भूस्खलन से राज्य को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की क्षति हुई। पुनर्निर्माण

शेष पृष्ठ 8 पर.....

सरकार का विरोध करते-करते प्रदेश हित भूली भाजपा: कांग्रेस

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी

शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि आरडीजी के मुद्दे पर भाजपा का वास्तविक चेहरा प्रदेश के सामने आ चुका है, जिससे वह बौखला गयी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में पंद्रहवें और सोलहवें वित्त आयोग के समक्ष सीमित संसाधनों और विशेष भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देकर आरडीजी की जोरदार वकालत करने वाले जय राम ठाकुर आज इसके विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं।

मंत्रियों ने प्रश्न उठाया कि कुछ ही महीनों में उनका रुख क्यों बदल गया। क्या भाजपा स्पष्ट करेगी कि वह आरडीजी को बंद करने के पक्ष में है या नहीं? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार का विरोध करते-करते भाजपा प्रदेश के हितों को ही भूल गई है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि को आर्थिक सहायता बताना भ्रामक है, क्योंकि यह प्रदेश का अधिकार है। आरडीजी हिमाचल का संवैधानिक अधिकार है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275(1) में है। उन्होंने स्मरण कराया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश को 56 हजार करोड़ रुपये आरडीजी तथा 14 हजार करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई थी, तब इस पर कोई आपत्ति नहीं थी।

मंत्रियों ने कहा कि विधानसभा में नियम 102 के तहत आरडीजी बहाली संबंधी सरकारी प्रस्ताव का विरोध कर भाजपा ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आपदा प्रभावितों

को विशेष आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव का समर्थन न करना भी इसी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा की इस दोहरी नीति को भली-भांति समझ चुकी है।

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के समापन की राज्यपाल ने की अध्यक्षता

शिमला/शैल। जिला मंडी में सप्ताह भर चले अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का समापन समारोह गरिमापूर्ण

ढंग से आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता शिव प्रताप शुक्ल ने की। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उपस्थित रहीं।

समारोह से पूर्व राज्यपाल ने ऐतिहासिक माधोराय मंदिर में पूजा-अर्चना की और पारंपरिक शोभायात्रा में भाग लिया। उन्होंने माता भीमाकाली परिसर स्थित देवलुधाम में श्रद्धा अर्पित की तथा श्री राज माधव राय मंदिर में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। सदियों पुरानी 'जलेब' शोभायात्रा में भी वे शामिल हुए और श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। राज्यपाल और लेडी गवर्नर ने पारंपरिक पगड़ी धारण कर जनता का स्वागत स्वीकार किया।

अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि यह मेला प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आस्था और परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने शिवरात्रि को आस्था, तपस्या और भक्ति का पर्व बताते हुए कहा कि भगवान शिव सृजन और संहार दोनों के प्रतीक हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर देते हुए कहा कि प्रकृति का सम्मान और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन ही सच्ची आराधना है।

राज्यपाल ने मंडी, जिसे 'छोटी काशी' के नाम से भी जाना जाता है, की आध्यात्मिक विरासत और प्राचीन मंदिरों की परंपरा की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह मेला लोक संस्कृति, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण मंच है।

मंडी नगर की स्थापना के 500 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित हेरिटेज वॉक, साहित्यिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक आयोजनों की भी उन्होंने प्रशंसा की। इस वर्ष महोत्सव में पंचवद्र मंदिर के निकट ब्यास आरती, मंडी के इतिहास पर आधारित लेजर शो, अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक दलों की भागीदारी, 'छोटी काशी साहित्य महोत्सव' और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाली पहलों को विशेष आकर्षण बताया गया।

राज्यपाल ने जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि जलेब की प्राचीन परंपरा को सुरक्षित रखने और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। उन्होंने बताया कि 200 से अधिक देवी-देवताओं की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष आध्यात्मिक गरिमा प्रदान की।

इस अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने भगवान शिव की महिमा पर आधारित नृत्य प्रस्तुति दी। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर का स्वागत करते हुए सप्ताह भर के कार्यक्रमों की जानकारी दी। राज्यपाल ने शिवरात्रि महोत्सव का ध्वज मेला समिति को सौंपकर मेले के समापन की औपचारिक घोषणा की।

समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या में राज्यपाल की शिरकत

शिमला/शैल। शिव प्रताप शुक्ल ने अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि

महोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उनके साथ उपस्थित रहीं।

आदिदेव महादेव को समर्पित इस सांस्कृतिक संध्या में भक्ति और उत्साह का विशेष माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी रहे। उनकी शिव स्तुति और लोकप्रिय भक्तिमय गीतों ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरे पंडाल में भक्ति रस और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण बना रहा।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं की जीवंत अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्सव प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करते हैं तथा एकता, भक्ति और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं।

कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की ओर से राज्यपाल और लेडी गवर्नर को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया।

शिमला नर्सिंग कॉलेज, में मानसिक स्वास्थ्य एवं मासिक धर्म स्वच्छता पर सेमिनार आयोजित

शिमला/शैल। शिमला नर्सिंग कॉलेज, शुराला में मानसिक स्वास्थ्य

एवं मासिक धर्म स्वच्छता विषय पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आदरणीय डॉ. किमी सूद के निर्देशन में तथा कॉलेज रेड क्रॉस टीम के सहयोग से संपन्न हुआ।

कार्यक्रम का संचालन हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम द्वारा किया गया। मुख्य वक्ताओं में विरेंद्र सिंह बिष्ट (राज्य जूनियर/युवा समन्वयक, मीनाक्षी मेहता (काउंसलर, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल), सुरेंद्र गौतम (सहायक सचिव, जिला रेड क्रॉस शाखा, शिमला) और अतुल नेगी (स्वयंसेवक, एच.पी.स्टेट रेड क्रॉस सोसायटी) शामिल रहे।

सेमिनार में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, तनाव प्रबंधन, अवसाद के लक्षणों की पहचान तथा समय पर परामर्श की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही मासिक धर्म स्वच्छता, उचित देखभाल, पोषण और सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने पर भी जागरूकता प्रदान की गई।

मीनाक्षी मेहता ने विद्यार्थियों से आहवान किया कि वे समाज में मानसिक स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। प्राचार्य डॉ. कृष्णा चौहान ने विद्यार्थियों को सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम नर्सिंग शिक्षा को व्यवहारिक और सामुदायिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाते हैं।

अंत में आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सेमिनार ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। कॉलेज परिवार ने सभी वक्ताओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

28 फरवरी से पूर्व ई-केवाईसी सुनिश्चित करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी

शिमला/शैल। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण (ईसोमसा) विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी सत्यापन नहीं करवाया है, वे 28 फरवरी 2026 से पूर्व अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र अथवा संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित ई-केवाईसी पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी न करवाने की स्थिति में संबंधित पेंशनभोगी को अनुपलब्ध अथवा अपात्र माना जाएगा और उसकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी।

प्रवक्ता ने कहा कि जिन पेंशनभोगियों का आधार कार्ड नहीं बना है या उसमें अद्यतन की आवश्यकता है, वे संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

ई-केवाईसी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक या संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

चंबा के बच्चों को मिलेगी आईसीएसई बोर्ड की शिक्षा सेंट स्टीफन स्कूल को मिली मान्यता

शिमला/शैल। चंबा शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल को आईसीएसई बोर्ड से आधिकारिक मान्यता मिल गई है। यह उपलब्धि क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा

के नए अवसर खोलेगी।

स्कूल प्रबंधन के अनुसार, संस्थान की स्थापना 1976 में मंडी में हुई थी और 2004 में चंबा में इसकी शुरुआत हुई। वर्ष 2016 में बनियाग में अपना परिसर तैयार होने के बाद 2017 से स्कूल वहीं संचालित हो रहा है। आईसीएसई मानकों को पूरा करने के लिए आधुनिक परीक्षा हॉल, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं तथा समृद्ध पुस्तकालय विकसित किए गए।

दो चरणों के निरीक्षण के बाद मान्यता प्रदान की गई।

आईसीएसई बोर्ड, जिसे (Council for the Indian School Certificate Examinations) भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद संचालित करता है, अपनी उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इसमें अंग्रेजी भाषा और साहित्य अलग विषय हैं तथा कक्षा छह से विज्ञान को तीन भागों में पढ़ाया जाता है। कक्षा नौ से विषय चयन की सुविधा भी उपलब्ध है।

स्कूल प्रबंधन ने इसे चंबा के शिक्षा जगत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर आधार मिलेगा।

डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती आधारित बीज उत्पादन पर कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। नौणी स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में 'सतत एवं लचीली कृषि हेतु प्राकृतिक खेती आधारित बीज उत्पादन' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें चंबा, मंडी, सिरमौर, हमीरपुर, शिमला और सोलन जिलों से किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के लगभग 200 किसानों ने भाग लिया।

कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि बीज कृषि की आधारशिला हैं और प्राकृतिक खेती में बीज स्वायत्तता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने देशी बीजों के संरक्षण, संवर्धन और सामुदायिक साझेदारी पर बल देते हुए किसान-नेतृत्व वाले बीज उद्यम विकसित करने का आहवान किया।

एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल एवं सीआईएटी के कंट्री प्रतिनिधि डॉ. जे.सी. राणा ने बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता को सतत कृषि का आधार बताया। उन्होंने सार्वजनिक संस्थानों, निजी हितधारकों और किसान समुदायों के बीच सहयोग की आवश्यकता रेखांकित की। साथ ही, हिमालयन एग्रोइकोलॉजी इनिशिएटिव (एचएआई) के माध्यम से हिमालयी क्षेत्र में लचीली खाद्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

पद्मश्री से सम्मानित प्रगतिशील किसान नेक राम शर्मा ने स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप देशी बीजों के संरक्षण पर बल दिया।

कार्यशाला में सामुदायिक प्रबंधित बीज बैंक स्थापित करने, पारंपरिक भंडारण पद्धतियों के पुनर्जीवन, देशी एवं लुप्तप्राय किस्मों के दस्तावेजीकरण, प्राकृतिक बीज उपचार प्रशिक्षण तथा बीज विनिमय कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।

विशेषज्ञ सत्रों में एग्रोइकोलॉजी, सामुदायिक बीज प्रणालियों और प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों पर विचार-विमर्श हुआ। इस पहल से जलवायु-लचीले बीजों की स्थानीय उपलब्धता बढ़ेगी, संकर बीजों पर निर्भरता घटेगी, कृषि जैव-विविधता को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों की आय में वृद्धि होगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

प्रदेश सरकार ने रोड ड्रेनेज पॉलिसी को दी स्वीकृति

दीर्घकालिक रणनीति के तहत सड़कों को किया जाएगा अधिक सुदृढ

शिमला/शैल। पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने व्यापक 'रोड ड्रेनेज पॉलिसी' को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुक्खविन्दर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में तैयार इस नीति का उद्देश्य सशक्त एवं टिकाऊ सड़क अधोसंरचना विकसित करना है, ताकि मानसून के दौरान होने वाले नुकसान को प्रभावी रूप से कम किया जा सके।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग 40,000 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क का रख-रखाव करता है। वर्ष 2023 और 2025 में भारी वर्षा के कारण सड़कों को क्रमश: लगभग 2400 करोड़ रुपये और 3000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ। तकनीकी आकलन में पाया गया कि अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था और भूस्खलन इसके प्रमुख कारण रहे।

नई नीति के अंतर्गत पारंपरिक प्रणाली के स्थान पर वैज्ञानिक हाइड्रोलॉजिकल एवं भू-आधारित डिजाइन सिद्धांत अपनाए जाएंगे। अब ड्रेनेज संरचनाएं वास्तविक वर्षा तीव्रता और जलग्रहण क्षेत्र के आंकड़ों के आधार पर डिजाइन की जाएंगी। इससे सड़क नेटवर्क की मजबूती, सार्वजनिक सुरक्षा और उपयोगिता में सुधार होगा।

सभी नई सड़क परियोजनाओं में ब क्स कल्वर्ट को डिफॉल्ट ड्रेनेज संरचना के रूप में अपनाया जाएगा। पहाड़ी ढलानों की स्थिरता, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में निवारक उपाय तथा ड्रेनेज प्रणाली को मुख्य इंजीनियरिंग घटक के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। आबादी वाले क्षेत्रों में मानकीकृत ढकी नालियां, ऊंचे कर्ब, इनलेट ओपनिंग और रिफ्लेक्टर लगाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

नीति का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से होगा, जिसमें आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, सड़कों की नालियों में अपशिष्ट जल, मलबा या निर्माण सामग्री डालने पर कड़ी कारवाई का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टिकाऊ अवसंरचना सुधार सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा और नागरिकों के लिए निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम है। यह नीति हिमाचल में सुरक्षित, लचीले और दीर्घकालिक सड़क नेटवर्क के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगी।

हिमाचल, जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों के हितों पर कुठाराघात है मुक्त व्यापार समझौते:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रीनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि हालिया

मुक्त व्यापार समझौते हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के किसानों व बागवानों के हितों के प्रतिकूल हैं। उनके अनुसार, इन समझौतों से सेब, अखरोट, बादाम और अन्य फलों के आयात में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय उत्पादकों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने में कठिनाई आ सकती है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों की बड़ी आबादी कृषि और बागवानी पर निर्भर है। हिमाचल में सेब उद्योग से लगभग 5,000 करोड़ रुपये का वार्षिक आर्थिक योगदान होता है और करीब 2.5 लाख परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हैं। ऐसे में आयात शुल्क में कमी का प्रभाव पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यूज़ीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ हुए समझौतों के तहत सेब और सूखे मेवों पर आयात शुल्क में कमी की गई है, जिससे स्थानीय किसानों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इसे किसानों के हितों के विरुद्ध बताया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों और बागवानों के मुद्दों को उठाती रही है और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

आपदा प्रभावितों को किराये हेतु 8.97 करोड़ रुपये जारी

घरों के पुनर्निर्माण के लिए 141.61 करोड़ की पहली किस्त वितरित

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 में भारी बारिश से प्रभावित उन परिवारों को राहत देने के लिए 8 करोड़ 97 लाख 90 हजार रुपये जारी किए हैं, जिनके मकान पूरी तरह टूट गए या रहने योग्य नहीं रहे। सरकार अपने संसाधनों से शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार 10 हजार रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार रुपये किराया सहायता दे रही है। इस सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों के 2,817 और शहरी क्षेत्रों के 88 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदा में प्रदेशभर के लगभग 16,488 परिवार प्रभावित हुए। इस दौरान 2,246 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 7,888 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली राहत राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। विशेष राहत पैकेज के तहत क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए 141 करोड़ 61 लाख रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। पिछले तीन वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश को लगभग 16,500 करोड़ रुपये से अधिक की क्षति हुई है।

सरकार ने पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए राहत राशि 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे और पक्के मकानों के लिए 1 लाख रुपये की सहायता निर्धारित की गई है। घरेलू सामान के नुकसान पर राहत राशि 2,500 रुपये से बढ़ाकर मकान मालिकों के लिए 1 लाख और किरायेदारों के लिए 50 हजार रुपये की गई है।

इसके अलावा, पॉलीहाउस के नुकसान पर 25 हजार रुपये तथा घरों से मलबा या गाद हटाने के लिए 50 हजार रुपये की सहायता का नया प्रावधान किया गया है।

प्रदेश सरकार ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, बिजली और पेयजल आपूर्ति को रिकॉर्ड समय में बहाल किया है। सरकार ने दोहराया है कि आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का विस्तार वंचित बेटियों को उच्च शिक्षा में सहयोग

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों के सामाजिक उत्थान को प्राथमिकता देते हुए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब विधवा महिलाओं की बेटियों को 27 वर्ष की आयु तक उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, चाहे वे प्रदेश में अध्ययन कर रही हों या राज्य से बाहर।

संशोधित प्रावधानों के तहत राज्य से बाहर सरकारी संस्थानों में व्यावसायिक पाठयक्रम कर रही छात्राओं को, छात्रावास उपलब्ध न होने पर, अधिकतम 10 माह तक प्रति माह 3,000 रुपये किराया/पीजी शुल्क के रूप में दिए जाएंगे।

वर्तमान में 18 से 27 वर्ष आयु वर्ग की 504 छात्राएं योजना का लाभ ले रही हैं। वित्त वर्ष के लिए योजना के तहत 31.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 3 फरवरी, 2026 तक 22.96 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है।

हिमाचल प्रदेश में खुदरा शराब ठेकों की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू

शिमला/शैल। प्रदेश में पहली बार खुदरा शराब ठेकों के आवंटन के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। राज्य सरकार ने पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस वर्ष ठेकों का आवंटन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से करने का निर्णय लिया है।

आबकारी विभाग के अनुसार, ई-नीलामी इकाई-वार आयोजित की जाएगी। प्रत्येक खुदरा आबकारी इकाई के लिए अलग-अलग ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। इच्छुक आवेदक घर या कार्यालय से ही ऑनलाइन आवेदन और बोली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। ई-नीलामी पोर्टल का लिंक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hptax.gov.in तथा आबकारी ई-गवर्नेंस पोर्टल https://egovef.hptax.gov.in पर उपलब्ध है। नीलामी https://eauction.gov.in/ngauction पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

पहले चरण में किन्नौर, हमीरपुर और चंबा जिलों के लिए आवेदन 23 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। दस्तावेजों की जांच 25 से 27 फरवरी तक होगी तथा नीलामी 28 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

सिरमौर, ऊना और बद्दी जिलों के लिए आवेदन 24 से 26 फरवरी तक, दस्तावेज जांच 26 से 28 फरवरी तक और नीलामी 2 मार्च 2026 को होगी। सोलन, कांगड़ा और बिलासपुर जिलों के लिए आवेदन 25 से 27 फरवरी तक, जांच 27 फरवरी से 2 मार्च तक तथा नीलामी 3 मार्च 2026 को निर्धारित है।

मंडी और नूरपुर क्षेत्रों के लिए आवेदन 26 से 28 फरवरी तक, दस्तावेज जांच 28 फरवरी से 3 मार्च तक तथा नीलामी 5 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। शिमला और कुल्लू जिलों के लिए आवेदन 27 फरवरी से 3 मार्च तक, दस्तावेज जांच 3 से 6 मार्च तक और नीलामी 7 मार्च 2026 को होगी।

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने बताया कि सभी आवेदकों के लिए वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) के माध्यम से पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने संभावित बोलीदाताओं से अपील की है कि वे आवेदन से पूर्व आबकारी नीति 2026-27, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और उपयोगकर्ता पुस्तिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। संबंधित दस्तावेज विभागीय वेबसाइट और ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

अंतरराष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव मंडी में सजी भव्य अंतरराष्ट्रीय कल्चरल परेड

शिमला/शैल। अंतरराष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव मंडी के तहत आयोजित अंतरराष्ट्रीय कल्चरल परेड

में 35 सांस्कृतिक दलों ने भाग लेकर शहर को रंग, संगीत और लोक परंपराओं से सराबोर कर दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उपायुक्त कार्यालय परिसर से परेड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परेड सेरी मंच से इंदिरा मार्केट तक पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने झांकियों का स्वागत किया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह महोत्सव आस्था के साथ-साथ सांस्कृतिक एकता और वैश्विक भाईचारे का प्रतीक है। विभिन्न देशों और राज्यों से आए कलाकारों की सहभागिता हिमाचल की अतिथि देवो भव: परंपरा को सुदृढ़ करती है।

अंतरराष्ट्रीय दलों में अर्जेंटीना, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका, रूस, अफ्रीकी देशों, वेनेजुएला, नेपाल, कजाकिस्तान और कंबोडिया के कलाकार शामिल रहे। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, असम और मणिपुर के दलों ने प्रस्तुति दी। प्रदेश के विभिन्न जिलों तथा मंडी के स्थानीय दलों ने भी लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत की।

रंग-बिरंगी वेशभूषा, लोक वाद्यों की मधुर धुनों और पारंपरिक नृत्यों ने पूरे शहर में उत्सव का माहौल बना दिया। यह परेड सांस्कृतिक विविधता और अंतरराष्ट्रीय सहभागिता का प्रभावी उदाहरण बनी।

कुपोषण मुक्त समाज की दिशा में सरकार की महत्त्वाकांक्षी पहल

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने माताओं और छोटे बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 207.11 करोड़ रुपये की लागत से 'इंदिरा गांधी मातृ-शिशु संकल्प योजना' शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत छ: वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, आवश्यक कैलोरी और सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त पूरक पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यभर में 2,99,488 पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

यह पहल जीवन के पहले 1,000 दिनों की महत्त्वपूर्ण अवधि पर केंद्रित होगी, ताकि पीढ़ी-दर-पीढ़ी चल रही कुपोषण की समस्या को समन्वित पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल सेवाओं के माध्यम से दूर किया जा सके। योजना का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर और रोगग्रस्तता को कम करना तथा समग्र पोषण स्तर में सुधार लाना है।

योजना के अंतर्गत गंभीर तीव्र कुपोषित और मध्यम तीव्र कुपोषित बच्चों, कम जन्म वजन वाले शिशुओं तथा अन्य उच्च जोखिम समूहों की शीघ्र पहचान, नियमित निगरानी और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सुदृढ़ रेफरल और अनुवर्ती तंत्र विकसित किया जाएगा।

फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को एनीमिया, दस्त और निमोनिया जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि वे गांव-गांव जाकर माताओं और बच्चों की सही देखभाल सुनिश्चित कर सकें। पोषण ट्रैकर और माता-शिशु सुरक्षा कार्ड के माध्यम से निगरानी की जाएगी।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जल शक्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच संस्थागत समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल सेवाओं की समेकित डिलीवरी सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कुपोषण खत्म करने के लिए गंभीर है और हर जरूरतमंद परिवार तक पौष्टिक आहार पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

किसी देश की महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।
.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

हिंसा और अराजकता राष्ट्रीय प्रश्नों के विकल्प नहीं हो सकते

लोकतंत्र तब खतरे में आ जाता है जब इसके सबसे बड़े मंच संसद में राष्ट्रीय प्रश्नों पर बहस न हो पाये। विपक्ष के सवालों का जवाब लोकसभा में न आ पाये। बल्कि इन सवालों से बचने के लिए प्रधानमंत्री लोकसभा में ही न आये। संसद के बाहर अराजकता, भय और हिंसा का वातावरण निर्मित होने में सरकार की सक्रिय भूमिका पर प्रश्न खड़े होने शुरू हो जाये। इस समय दुर्भाग्य से यह सब घट रहा है। राष्ट्रीय प्रश्नों को जब शीर्ष न्यायपालिका भी लंबाने की नीति पर चल पड़े तो निश्चित रूप से यह मानना ही पड़ेगा कि लोकतंत्र सही में खतरे में है। इस समय वोट चोरी से लेकर एपस्टिन फाइल तक जितने भी राष्ट्रीय प्रश्न उठे हैं एक पर भी संसद के अन्दर बहस नहीं हुई है। जब-जब यह सवाल उठे हैं तब-तब प्रधानमंत्री लोकसभा में आये ही नहीं। विपक्ष को लोकसभा में बोलने ही नहीं दिया गया। बल्कि कुछ महिला सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा हो सकता है यह जानकारी स्वयं लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री को देते हैं और प्रधानमंत्री लोकसभा में आने की बजाये राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन उन महिला सांसदों को चिन्हित करके उन पर कोई कारवाई नहीं की जाती है। संसद के बाहर एक भक्त इन सांसदों और राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मारने की बात करता है। पुलिस जब इस व्यक्ति के खिलाफ कारवाई करती है तब इसका आपराधिक रिकॉर्ड सामने आता है। इसी तरह एक सनातन सम्मेलन में जहां पर धार्मिक उन्माद और वैमनस्य बढ़ाने के आयोजकों द्वारा भाषण दिये जाते हैं तब आरटीआई की एक सूचना के माध्यम से यह जानकारी आती है कि इस सनातन सम्मेलन को संस्कृति मंत्रालय द्वारा तरेसठ लाख का अनुदान दिया गया है। इस सम्मेलन में हिन्दू राष्ट्र के लिये धार्मिक वैमन्सय का वातावरण निर्मित किया जाता है। ऐसे और भी कई प्रसंग है जहां हिन्दू राष्ट्र के लिये धार्मिक और जातीय भेदभाव को उकसाया गया है। ऐसे संकेत और संदेश उभर रहे हैं जहां हिन्दू राष्ट्र के लिये धार्मिक और जातिय हिंसा को बढ़ावा देने के उपक्रम किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय प्रश्नों को हिंसा और अराजकता से दबाने के खुले प्रयास हो रहे हैं। सरकार कब तक राष्ट्रीय प्रश्नों से बचती रहेगी यह अब एक आम चर्चा का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि जिस अनुपात में इन प्रश्नों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है उस अनुपात में यह सवाल और बड़े होते जा रहे हैं। सरकार की इस नीति और नीयत के कारण ही आज स्थितियां लोकसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव तक आ गये हैं। आज जिस तरह से अमेरिका के साथ हुये व्यापार समझौते में देश के किसान पर संकट आया है। उससे किसान के पास सड़क पर उतरने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होगा। कृषि कानूनों के विरोध में देश किसान आन्दोलन को देख चुका है और सरकार भोग चुकी है। अब अमरिकी व्यापार समझौते के साथ ही पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवाणे की किताब का मुद्दा भी सरकार से जवाब मांग रहा है। जिस तरह से यह किताब चर्चा में आई है उसके परिणामस्वरुप इसका कथ्य हर आदमी तक पहुंच गया है। सरकार राष्ट्रीय प्रश्नों से बचने के लिये जितने प्रयास कर रही है उसके कारण उसकी हिन्दू राष्ट्र की मंशा जन चर्चा में आती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ढंग से पूरी भाजपा का प्राय: बन गये थे आज शायद पूरी भाजपा उनके अपने ही भार से दबने के कगार पर पहुंचती जा रही है। यही स्थिति भाजपा के लिये नुकसानदेह होगी। क्योंकि राष्ट्रीय प्रश्नों के साथ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे जुड़ जाएंगे। व्यवहारिक रूप से इन मुद्दों का आकार आज 2014 से कई गुना बढ़ गया है। इस बढ़ते आकार के साये में राष्ट्रीय प्रश्नों पर बहस की मांग को हिंसा और अराजकता से दबाना असंभव हो जाएगा।

विरासत केवल आयोजन नहीं, विश्व मानवता को आपस में जोड़ने वाला संस्कृतिक संगम है : राजीव कुमार सिंह

साक्षात्कार

गौतम चौधरी

विगत दिनों देहरादून प्रवास के दौरान रीच के संस्थापक और विरासत नामक सांस्कृत आयोजन के प्रमुख संचालक राजीव कुमार सिंह (अपनों के बीच 'आर.के.') से हुई लंबी बातचीत औपचारिक शुरुआत के बाद शीघ्र ही आत्मीय संवाद में बदल गई। सामाजिक-सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़े राजीव जी इन दिनों अपना समय चार हिस्सों में बांटते हैं, परिवार, पैतृक गांव बेलसंडी, ससुराल मंझौल, देहरादून-दिल्ली और विविध सांस्कृतिक गतिविधियां। संस्कृति, राष्ट्र, कला और 'विरासत' की यात्रा पर उनसे हुई यह सारगर्भित प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत है।

आप 'विरासत' क्यों करते हैं?

अब तो यह मेरे जीवन की लत बन चुकी है, इसे छोड़ना संभव नहीं। व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है-हम इसी अंतराल को जीवन मान लेते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन वह है, जो जन्म और मृत्यु के बीच आपके द्वारा किया गया वह काम है, जिसका प्रभाव हमारे चारोतरफ के वातावरण पर पड़ता है।

मानव सभ्यता का मूल तत्व आनंद है। बसंत में प्रकृति का उल्लास इसका प्रमाण है। कला, संगीत और साहित्य इसी आनंद की अभिव्यक्ति हैं- और यही सभ्यता का सार है। विज्ञान जीवन को आसान बनाता है, पर कला और संस्कृति जीवन को अर्थ देती हैं, जीने की संरचना देती हैं। मैं 'विरासत' इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे जीवन को आनंदपूर्वक जीना है-और उस आनंद को बांटना है।

'विरासत' में आप कला के गंभीर पक्ष को ही प्रमुखता देते हैं। ऐसा क्यों?

यही भारतीयता है। भारत का अर्थ ही है-'जो ज्ञान में रत रहे'। हमारा राष्ट्रवाद पश्चिमी अवधारणा से भिन्न है। हमारी संस्कृति में शास्त्रीयता, मर्यादा और सौंदर्य है। फूहरपन और अश्लीलता हमारी पहचान नहीं है।

मैं एक ऐसी पारिवारिक परंपरा से आता हूं जहां धर्म, संस्कृति और कला के संरक्षण को दायित्व माना गया। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान और परंपरा को बचाने का कार्य किया। वही हमारी जातीय जिम्मेदारी है। इसलिए 'विरासत' के मंच पर हम सतही या सस्ती चीजें प्रस्तुत नहीं करते। कठिनाइयां आती हैं, पर मूल्यों से समझौता नहीं होगा।

भारतीय कला को आप किस दृष्टि से देखते हैं?

राष्ट्र केवल भू-भाग नहीं है, वह अनादि काल से विकसित होती चेतना है। सिंधू घाटी की सभ्यता से अब तक जो सांस्कृतिक निरंतरता हमें मिली है, भारतीय कला उसी की अभिव्यक्ति है। यह कला आत्मा को परम तत्व तक विस्तार देती है और मुक्ति का मार्ग दिखाती है।

ज्ञान की रक्षा कठिन परिस्थितियों में भी की गई-चाहे संसाधन कम रहे हों। हम भी अपने हिस्से के भारत को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृति का संरक्षण केवल हस्तांतरण से नहीं, बल्कि आमजन की स्वीकार्यता से संभव है। मेरा प्रयास भारतीय संस्कृति के आवश्यक स्वरूप को समाज के बीच प्रतिष्ठित करना है।

'विरासत' की यात्रा कैसे शुरू हुई?

मैं Oil and Natural Gas Corporation (ओएनजीसी) में पदाधिकारी था और एक सांस्कृतिक संस्था से जुड़ा हुआ था, पर मुझे हर वक्त कुछ नया करने की इच्छा हो रही थी। जो करना चाहता था, वह संभव नहीं हो पा रहा था। तब कुछ मित्रों के साथ मिलकर रूलर इंटरप्रेनियोरशिप फॉर आर्ट्स एंड हेरिटेज 'रीच' की स्थापना की और 'विरासत' का शुभारंभ किया।

भारतीय शास्त्रीय और लोक कलाओं को मंच देना हमारी प्राथमिकता रही है। बिना आर्थिक गारंटी के, तीन दशकों से निरंतर चलने वाला यह आयोजन अपने आप में अनूठा है। 'विरासत' के मंच पर देश-विदेश के अनेक श्रेष्ठ कलाकारों ने प्रस्तुति दी है-शास्त्रीय संगीत, लोक कला, शिल्प, चित्रकला, साहित्य, सिनेमा, नाटक, लोकनृत्यु और संगीत-सभी को समग्रता से स्थान मिला है। सीमित संसाधनों में भी हमने प्रयोग किए हैं, जिनका सांस्कृतिक महत्व व्यापक है।

आर्थिक चुनौतियों का समाधान कैसे निकालते हैं?

यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। शुरुआत से ही हमलोग आर्थिक संकट से जूझते रहे हैं। सरकारी, खास कर ओएनजीसी का अनुदान हमारा आधार रहा है, पर वह भी लगातार कम हो रहा है। सांस्कृतिक आयोजनों में प्रत्यक्ष मुनाफा नहीं होता, इसलिए निजी क्षेत्र की कंपनियाँ आगे नहीं आतीं। लेकिन निजी सहयोग के बिना दीर्घकालिक निरंतरता संभव नहीं है। सांस्कृतिक आयोजनों में निजी क्षेत्र का निवेश जरूरी है। दरअसल, इसे महज सांस्कृतिक आयोजन नहीं समझा जाना चाहिए। यह विश्व शांति का आधार है। इस प्रकार के आयोजन सांस्कृतिक सेतु का काम करते हैं। इसमें किया गया निवेश दीर्घकालिक है। इसलिए निजी क्षेत्रों के उद्योजकों को हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। मुझे ईश्वर पर विश्वास है। विश्वास है कि यह संकट भी दूर होगा।

-राजीव कुमार सिंह-

आगे की आपकी क्या योजना है?

पहला लक्ष्य आर्थिक आत्मनिर्भरता है। उसके बाद इस आयोजन को वैश्विक स्वरूप देना है।

यदि कॉरपोरेट जगत और सरकार सकारात्मक सहयोग करें, तो हम इसे विश्वस्तरीय सांस्कृतिक संगम बना सकते हैं। हमारे पास कला का वह ज्ञान है, जो हमें 'विश्व गुरु' के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है लेकिन उसके लिए हमें अपने व्याप को बड़ा करना होगा और कसौटी की संकीर्णता समाप्त करनी होगी। विश्व गुरु बनने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सांस्कृतिक आयोजन उसका अहम पक्ष है। हम अपने हिस्से का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में हर को अपनी आहुति देनी चाहिए।

इतने बड़े आयोजन का प्रबंधन कैसे करते हैं? (हसते हुए)

आप भूल रहे हैं कि मैं ओएनजीसी जैसे विशाल उपक्रम के प्रबंधन से जुड़ा रहा हूँ। हम 'क्रिएटिविटी' का प्रबंधन करते हैं-इसे आप 'सकारात्मक रुचि का व्यापार' भी कह सकते हैं।

हमने अपने आयोजन की एक विशिष्ट कार्य-संस्कृति विकसित की है-जहां परंपरा और प्रयोग का समन्वय है। आधुनिकता और पुरातन का संतुलित योग ही 'विरासत' की पहचान है। हमारी कार्यशैली पर शोध भी किया जा सकता है।

अंत में क्या कहना चाहेंगे?

हमारा उद्देश्य है-ईश्वरीय आनंद की अनुभूति से आमजन को परिचित कराना। इसके लिए समाज का सहयोग आवश्यक है।

''शैल'' साप्ताहिक के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित विवरण

1. प्रकाशन स्थान	:	शैल कार्यालय ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज, लक्कड़ बाजार शिमला
2. प्रकाशन अवधि	:	साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	:	बलदेव शर्मा
4. राष्ट्रीयता	:	भारतीय
5. प्रकाशक का नाम	:	बलदेव शर्मा
6. पता	:	ऋचा पिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज, रिवोली बस स्टैण्ड लक्कड़ बाजार शिमला
7. सम्पादक का नाम	:	बलदेव शर्मा
8. उन व्यक्तियों के नाम और पते जो समाचार पत्र के स्वामी और भागीदार या कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक सांझेदार/हिस्सेदार हों	:	कोई नहीं

मैं बलदेव शर्मा घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

(बलदेव शर्मा)

पारदर्शिता से जवाबदेही की ओर: भारत की खाद्य सुरक्षा संरचना में एआई की भूमिका

– संजीव चोपड़ा –
सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

पिछले एक दशक के दौरान, भारत ने अभूतपूर्व पैमाने पर अपनी खाद्य सुरक्षा संरचना का डिजिटलीकरण किया है। खरीद एवं भंडारण से लेकर परिवहन, वितरण और सब्सिडी के निपटारे तक, मूल्य श्रृंखला का हर चरण अब डिजिटल प्रणालियों द्वारा संचालित है।

यह व्यवस्था निरंतर संचालन से जुड़े आंकड़े सृजित करने के साथ-साथ ही हर महीने लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान कर रही है।

शासन संबंधी अगली चुनौती इस पारदर्शिता को प्रशासनिक जवाबदेही में बदलना है। सिर्फ दृश्यता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस प्रणाली को पैटर्न की व्याख्या करने, जोखिमों को प्राथमिकता देने और समय पर प्रतिक्रिया देने में भी समर्थ होना चाहिए। इस बदलाव को देखते हुए, केन्द्र सरकार पूरी प्रणाली में निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग कर रही है।

खरीद प्रक्रिया के दौरान, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को कुटाई के बाद आपूर्ति किये गये चावल की गुणवत्ता का आकलन टूटे हुए दानों के प्रतिशत, अशुद्धियों और रंग में बदलाव जैसे निर्धारित मापदंडों के आधार पर दृश्य आधारित मूल्यांकन पर निर्भर करता है। बड़े पैमाने पर, मानवीय व्यक्तिपरकता के कारण नतीजे भिन्न हो सकते हैं।

इसलिये, एआई से लैस स्वचालित अनाज विश्लेषक (एजीए) का उपयोग तस्वीर-आधारित विश्लेषण के जरिए इन मापदंडों का आकलन करने हेतु किया जा रहा है। माप को मानकीकृत और व्यक्तिपरकता को कम करके, ये प्रणालियां मौजूदा खरीद मानदंडों के भीतर काम करते हुए गुणवत्ता के सत्यापन में निरंतरता को बेहतर बना रही हैं।

एफसीआई और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी) द्वारा संचालित भंडारण केन्द्रों में, निगरानी को मजबूत करने हेतु आईओटी-आधारित निगरानी प्रणालियों की शुरुआत की जा रही है। सेंसर तापमान, आर्द्रता, फॉस्फीन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को मापते हैं, जबकि एआई से लैस कंप्यूटर विजन टूल स्वचालित तरीके से बोरियों की गिनती और स्टॉक के सत्यापन में सहायता करते हैं। ये प्रणालियां माल-सूची (इन्वेंट्री) और पर्यावरणीय स्थितियों से संबंधित निरंतर आंकड़े सृजित करती हैं। डीएफपीडी के वेयरहाउस ग्रेडिंग प्लेटफॉर्म, डिपो दर्पण के साथ एकीकृत, इस आंकड़े का विश्लेषण प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का उपयोग करके खराब होने के जोखिम, स्टॉक संबंधी विसंगतियों या अनुपालन की कमियों से जुड़े पैटर्न की पहचान करने हेतु किया जा सकता है ताकि शीघ्र और अपेक्षाकृत अधिक जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण से जुड़ी कारवाई संभव हो सके।

खाद्यान्नों की आवाजाही के दौरान, मार्ग अनुकूलन उपकरणों ('अन्न चक्र') का उपयोग करके जहां परिवहन की योजना बनाई जाती है, वहीं व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटीएस) ट्रक की आवाजाही से जुड़े वास्तविक समय में जीपीएस आधारित आंकड़े सृजित करते हैं। राज्यों ने मार्ग अनुकूलन के जरिए लगभग 238 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत की है। मार्ग संबंधी योजना भले ही व्यवस्थित है, लेकिन राज्यों में हजारों यात्राओं की निगरानी करना परिचालन संबंधी चुनौतियां पेश करता है। आवागमन संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करने और बार-बार होने वाले मार्ग विचलन, असामान्य देरी या असामान्य ठहराव को चिह्नित करने के उद्देश्य से एआई-आधारित पैटर्न का पता लगाने और विसंगति की पहचान करने की योजना बनाई जा रही है। ये विश्लेषण निगरानी को मजबूत कर रहे हैं और परिवहन संचालन के अपेक्षाकृत अधिक केन्द्रित सत्यापन को संभव बना रहे हैं। वितरण वाले चरण में, राज्यों द्वारा रखे गए लाभार्थियों के रिकॉर्ड को स्मार्ट-पीडीएस प्लेटफॉर्म के तहत समेकित किया जाता है। इससे राशन कार्डो का एक एकीकृत राष्ट्रीय भंडार तैयार होता है। यही नहीं, इससे राज्य द्वारा परिभाषित मानदंडों के तहत संभावित रूप से अपात्र कार्डो की पहचान करने हेतु अन्य सरकारी डेटाबेस के साथ सत्यता की पुष्टि (क्रॉस-वेरिफिकेशन) भी संभव हो पाती है। अब तक, इस तरह के सत्यापन के जरिए 8.51 करोड़ राशन कार्डो को चिह्नित किया गया है। इनमें से 2.18 करोड़ कार्डो को राज्य सरकारों द्वारा उचित प्रक्रिया के बाद हटा दिया गया है। हालांकि नामों, पतों, आधार सीडिंग और परिवार की संरचना में विसंगतियां बड़े पैमाने पर नियम- आधारित जांच की प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं। संभावित नकल, संबंधित पहचानों या परिवारों के असामान्य पुनर्गठन की पहचान करने हेतु मशीन लर्निंग पर आधारित आंकड़ों के मिलान की तकनीकों का उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले जोखिम संबंधी संकेत राज्यों द्वारा लक्षित सत्यापन में सहायता करेंगे, जिससे मौजूदा पात्रता संबंधी मानदंडों के भीतर सटीकता बेहतर होगी।

लाभार्थियों की शिकायतें सेवाओं की आपूर्ति और अनाज की गुणवत्ता के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। शिकायत दर्ज कराने हेतु कई साधन (ऑनलाइन पोर्टल, कॉल सेंटर, व्हाट्सएप और आईवीआरएस सहित) मौजूद हैं, लेकिन शिकायतों की संख्या और भाषाई विविधता के कारण समय पर उनका निपटान और समाधान करना मुश्किल हो जाता है।

सरकार ने अन्न सहायता होलिस्टिक एआई सॉल्यूशन (आशा) शुरू किया है, जो बहुभाषी वॉयस आउटरीच और एआई-आधारित विश्लेषण का उपयोग करके लाभार्थियों से व्यवस्थित प्रतिक्रिया एकत्र करता है। स्वचालित वर्गीकरण और भावनाओं के विश्लेषण प्रशासकों के लिए डैशबोर्ड तैयार करते हैं, जिससे प्राथमिकता के निर्धारण और प्रतिक्रिया में लगने वाले समय में सुधार होता है। आशा वर्तमान में प्रति माह लगभग 20 लाख लाभार्थियों तक पहुंचती है और पूरे देश में इसका विस्तार किया जा रहा है। अंत में, राज्य सरकारें खरीद लागत घटकों से संबंधित सहायक दस्तावेजों के साथ एनएफएसए के लिए सब्सिडी दावे (स्कैन) पोर्टल के जरिए सब्सिडी संबंधी दावों को प्रस्तुत करती हैं। प्रारूप और चेकलिस्ट भले ही मानकीकृत हैं, लेकिन अपूर्ण, बेमेल या अस्पष्ट दस्तावेज के कारण जांच और प्रतिपूर्ति में देरी हो सकती है। दस्तावेजों की प्रासंगिकता, डेटा की निरंतरता और अपलोड की स्पष्टता की पुष्टि करने हेतु एआई-आधारित दस्तावेज सत्यापन और गुणवत्ता मूल्यांकन का उपयोग किया जा रहा है। इससे बार-बार की पूछताछ कम होती है और दावों के निपटारे की प्रक्रिया में दक्षता और निरंतरता बेहतर होती है।

भारत की खाद्य सब्सिडी संरचना ने डिजिटलीकरण के जरिए पहले ही बर्बादी को कम कर दिया है। अगला बदलाव जवाबदेही में निहित है। खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और दावों के निपटान की प्रक्रिया में एआई को शामिल करके, यह प्रणाली जोखिमों का शीघ्र पता लगाने, त्रुटियों को तेजी से सुधारने और लाभार्थियों को उनका हक समय पर दिलाने में अधिक समर्थ हो जाती है। कुल 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले इस कार्यक्रम में, अधिक जवाबदेही कोई मामूली सुधार नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा ढांचे की संरचनात्मक मजबूती का प्रतीक है।

रंग, रस और राग का उत्सव
सुजानपुर टीहरा की ऐतिहासिक होली

राजन कुमार शर्मा

हमीरपुर जिला की सांस्कृतिक पहचान उसकी जीवंत लोकपरंपराओं में निहित है, और सुजानपुर टीहरा की होली इसी पहचान का सबसे उज्ज्वल और गरिमामय उत्सव है। यह पर्व केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि इतिहास, लोकसंवेदना, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना का सजीव प्रतीक है।

जब बसंत की मादक बयार हिमालय की तराइयों को स्पर्श करती हुई सुजानपुर टीहरा की गलियों में उतरती है, तब यह ऐतिहासिक नगरी केवल ऋतु परिवर्तन का साक्ष्य नहीं बनती, बल्कि रंग, रस और राग से परिपूर्ण एक विराट उत्सवभूमि में परिवर्तित हो जाती है। सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं मानो एक साथ जाग उठती हैं और पूरा नगर उल्लास के रंगों में डूब जाता है।

कटोच वंश की गौरवशाली विरासत को संजोये यह नगर जब होली के रंगों से सुसज्जित होता है, तब इसके प्राचीन दुर्ग, मंदिर और ऐतिहासिक चौक इतिहास और वर्तमान के अद्भुत संगम के साक्षी बनते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो समय स्वयं ठहरकर इस उत्सव का रसास्वादन कर रहा हो।

सुजानपुर टीहरा की होली का स्वरूप राजाश्रय से पुष्पित-पल्लवित हुआ। राजदरबारों में आरंभ हुआ यह उत्सव कालांतर में लोकजीवन में रच-बस गया। आज भी इसमें उस राजसी गरिमा की झलक मिलती है, जहां संस्कृति केवल आयोजन नहीं, बल्कि जीवनशैली हुआ करती थी। यह होली अतीत और वर्तमान के बीच एक सशक्त सेतु के रूप में दिखाई देती है।

होली के दिनों में नगर का प्रत्येक प्रांगण एक रंगमंच में बदल जाता है। ढोल-नगाड़ों की थाप, बांसुरी की मधुर तान और लोकगीतों की स्वर-लहरियां वातावरण को रसमय बना देती हैं। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकार जब मंच पर उतरते हैं, तो लोकसंस्कृति साकार रूप ले लेती है। यहां रंग केवल चेहरे पर नहीं, बल्कि मन और आत्मा पर चढ़ते हैं। हंसी, विनोद, व्यंग्य और श्रृंगार रस से भरपूर प्रस्तुतियां दर्शकों को आनंद और आत्ममंथन दोनों का अनुभव कराती हैं।

यह उत्सव सामाजिक एकता का उद्घोष भी है। होली के दिन भेदभाव की दीवारें स्वत: ढह जाती हैं। अमीर-गरीब, युवा-वृद्ध, स्त्री-पुरुष-सभी एक ही रंग में रंगे दिखाई देते हैं। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसकी सहृदयता, सामूहिकता और परस्पर सम्मान में निहित है।

सुजानपुर टीहरा की होली सांस्कृतिक संवाद की एक सतत प्रक्रिया है। वरिष्ठ पीढ़ी अपने अनुभवों और परंपराओं के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ती है। लोकगीतों की पंक्तियों में इतिहास बोलता है और नृत्य की थाप पर भविष्य कदमताल करता है।

आज यह होली क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर व्यापक पहचान बना चुकी है। दूर-दराज़ से आने वाले पर्यटक इस सांस्कृतिक ऊष्मा को आत्मसात कर लौटते हैं। यह उत्सव न केवल सांस्कृतिक चेतना को समृद्ध करता है, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार करता है।

सुजानपुर टीहरा की होली जीवन का उत्सव है-जहां रंग केवल चेहरे पर नहीं, विचारों में घुलते हैं, जहां गीत केवल कानों में नहीं, आत्मा में उतरते हैं। परंपरा जब संवेदना से जुड़ती है, तब वह मात्र स्मृति नहीं रहती, बल्कि जीवंत सांस्कृतिक विरासत बन जाती है। इसी विरासत का रंगीन, रसपूर्ण और गरिमामय स्वरूप है-सुजानपुर टीहरा की ऐतिहासिक होली।

शिवरात्रि मेला में प्राकृतिक खेती स्टॉल बना जन-जागरूकता का केंद्र
रसायनरहित 'हिमभोग' आटा बिक्री के लिए उपलब्ध

धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेला, मंडी में इस वर्ष कृषि जागरूकता का विशेष आयाम जुड़ा है। कृषि विभाग की एटीएमए परियोजना की ओर से

पड्डल मैदान स्थित प्रदर्शनी पंडाल में प्राकृतिक खेती को समर्पित विशेष स्टॉल स्थापित किया गया है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने किया। यह स्टॉल एक सप्ताह तक आमजन के लिए खुला रहेगा।

स्टॉल पर प्राकृतिक खेती की विधि, लाभ और अपनाने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। कृषि विशेषज्ञ आगंतुकों को रसायनमुक्त खेती के महत्व से अवगत कराते हुए इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

मुख्य आकर्षण प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की और गेहूं के 'हिमभोग' ब्रांड का पोषणयुक्त, रसायनरहित आटा है, जिसे पहली बार मेले में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। श्रद्धालु और पर्यटक इसकी जानकारी लेने के साथ इसे खरीद भी रहे हैं।

स्टॉल पर जीवामृत, घनजीवामृत और बीजामृत जैसे पारंपरिक घटकों की जानकारी प्रदर्शित की गई है। साथ ही राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत किसानों को मिल रहे लाभों से भी अवगत कराया जा रहा है।

जिला परियोजना निदेशक, एटीएमए, डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक खेती के प्रति व्यापक जन- जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह पद्धति मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित अन्न उत्पादन में सहायक है।

मेले में उमड़ी भीड़ के बीच यह स्टॉल स्वास्थ्य, पर्यावरण और टिकाऊ कृषि का प्रभावी संदेश दे रहा है तथा लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहा है।

एंटी-चिट्टा अभियान के तहत 96 आदतन व संगठित तस्कर निरुद्ध

नशा तस्करी के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पुलिस का व्यापक अभियान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुखविन्द्र सिंह सुक्खू द्वारा शुरू किए गये प्रदेशव्यापी एंटी-चिट्टा अभियान के अंतर्गत संगठित नशा तस्करी के विरुद्ध व्यापक और समन्वित कारवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा पीआईटी एंड एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 19 फरवरी को आठ कुख्यात नशा तस्करों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक (इनहिबिटरी) आदेश जारी किए गए थे, जिनका आज सफल क्रियान्वयन किया गया। इस दौरान जिला शिमला से पांच, देहरा से एक, नूरपुर से एक तथा ऊना से एक तस्कर को निरुद्ध (डिटेन) किया गया। यह अभियान बहु-जिला समन्वय, सटीक खुफिया सूचना और विधिक रणनीति के आधार पर संचालित किया गया, जिससे संगठित नशा आपूर्ति नेटवर्क को प्रभावी रूप से बाधित किया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2025 के अंत तक पीआईटी एंड एनडीपीएस एक्ट के तहत 65 नशा तस्करों को निरुद्ध किया गया था, जबकि वर्ष 2026 में अब तक 31 तस्करों के विरुद्ध कारवाई की जा चुकी है। इस प्रकार अब तक कुल 96 आदतन और संगठित तस्करों को इस कानून के अंतर्गत निरुद्ध किया जा चुका है।

इन तस्करों की चल-अचल संपत्तियों की विस्तृत वित्तीय जांच जारी है। अवैध आय से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर विधि अनुसार जब्ती और कुर्की की कारवाई की जाएगी, ताकि उनके आर्थिक नेटवर्क को भी समाप्त किया जा सके।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में नशा तस्करी के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत आगे भी ऐसे लक्षित और समन्वित अभियान जारी रहेंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि नशे से संबंधित किसी भी सूचना को तुरंत 112 या नजदीकी पुलिस थाना में साझा करें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

पीएमजीएसवाई-IV के तहत 1,500 किमी सड़कों की स्वीकृति

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत प्रदेश में संचालित परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

बैठक में उन्होंने डोडरा क्वार क्षेत्र की लंबित सड़क परियोजनाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित कार्य अवधि के कारण पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत स्वीकृत सड़क का कुछ भाग अभी शेष है, जबकि यह मार्ग स्थानीय ग्रामीणों, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लंबित पैकेजों के लिए विशेष छूट, अतिरिक्त वित्तीय सहयोग और तकनीकी सहायता का आग्रह किया।

मंत्री ने बताया कि पीएमजी एसवाई-IV के तहत हिमाचल को लगभग 1,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति मिली है, जिनकी अनुमानित लागत 2,300 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, अगले चरण में लगभग 1,200 किलोमीटर नई सड़कों का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों और भूमि-स्वामियों से गिफ्ट डीड के माध्यम से सहयोग की अपील की, ताकि सड़क निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण हो सके।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि लंबित कार्यों और वित्तीय अनुमोदनों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।

2.25 करोड़ की लागत से विद्यालय भवनों के शिलान्यास व लोकार्पण

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने चम्बा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 करोड़ 25 लाख रुपये की धनराशि से निर्मित एवं प्रस्तावित विभिन्न विद्यालय भवनों के शिलान्यास और लोकार्पण किए। इस अवसर पर विधायक नीरज नैय्यर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

शिक्षा मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चनेड में 1 करोड़ 96 लाख रुपये की लागत से बनने वाले विज्ञान खंड का शिलान्यास किया। इसके उपरांत उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय साच में लगभग 29 लाख रुपये से निर्मित अतिरिक्त भवन का लोकार्पण किया।

उन्होंने राइजिंग स्टार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उदयपुर में नए ऑडिटोरियम, क्रिकेट कोर्ट और कन्या छात्रावास 'गुरुकुल' का भी शुभारंभ किया तथा विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया।

अपने प्रवास के दौरान शिक्षा मंत्री ने जीएसएसएस चनेड, साच तथा राइजिंग स्टार स्कूल उदयपुर में विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में गुणवत्ता युक्त और परिणामोन्मुख शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 की तुलना में वर्तमान में प्रदेश की साक्षरता दर 99.30 प्रतिशत तक पहुंच गई है। गत तीन वर्षों में शिक्षा विभाग में 7 हजार पदों पर नियुक्तियां की गई हैं, जबकि 4 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सर्वाधिक नामांकन चंबा जिले में है, जो शिक्षा विभाग के प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में चयनित 42 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए 112 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विधायक नीरज नैय्यर की मांग पर शिक्षा मंत्री ने राजकीय उच्च पाठशाला पल्युर के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए 11 लाख रुपये देने की घोषणा की।

कार्यक्रम के दौरान मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मंत्री ने विज्ञान खंड निर्माण हेतु एक बीघा भूमि दान करने वाली इसरो देवी तथा विद्यालय शौचालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने वाले सुरजीत कुमार को भी सम्मानित किया। साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए जीएसएसएस चनेड को 15 हजार रुपये देने की घोषणा की।

इस अवसर पर पूर्व विधायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, उपायुक्त, एसपी, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

नगर निगम शिमला का 688.02 करोड़ का बजट पेश, विकास कार्यों पर जोर

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 688.02 करोड़ रूपये का वार्षिक बजट पेश किया। बजट में शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने, पार्किंग सुविधाओं के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं के लिए भी राशि निर्धारित की गई है।

बजट प्रावधानों के अनुसार कच्चीघाटी में वेलनेस सेंटर के लिए 66 करोड़ रूपये, बालूगंज में 72 स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिए 34 करोड़ रूपये तथा रेजिडेंशियल फ्लैट निर्माण के लिए 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मल्टी-पर्पज मॉडर्न कॉम्प्लेक्स के लिये 140 करोड़ रूपये निर्धारित किये गये हैं।

शहर में 1,000 सोलर स्ट्रीट लाइटें स्थापित करने और भरयाल क्षेत्र में 2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना भी बजट में शामिल है। ई-निगम प्रणाली लागू करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और ठोस कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए भी राशि निर्धारित की गई है।

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, हालांकि कुछ उपयोग शुल्कों में वृद्धि की गई है।

निगम ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। बजट को विकासोन्मुख बताते हुए निगम ने शहरवासियों से सहयोग की अपील की है।

अंतरराष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव मंडी के अवसर पर सड़क सुरक्षा रैली आयोजित

शिमला/शैल। अंतरराष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव मंडी-2026 के तहत परिवहन विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सेरी मंच से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

रैली सेरी मंच से प्रारंभ होकर मंगवाई, चक्कर और नेरचौक होते हुए डडौर में संपन्न हुई। इसमें 50 बाइक और 25 कारों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने निर्धारित गति और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वाहन चलाए।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन औसतन लगभग छह सड़क दुर्घटनाएं दर्ज होती हैं, जिनमें करीब दो लोगों की मृत्यु और नौ लोग घायल होते हैं। अधिकांश हादसे ओवरस्पीडिंग, नशे में वाहन चलाने, गलत दिशा में ड्राइविंग तथा मोबाइल फोन के उपयोग के कारण होते हैं। उन्होंने विशेष चिंता व्यक्त की कि लगभग 70 प्रतिशत दुर्घटनाएं 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग से संबंधित हैं।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि सीट बेल्ट और हेलमेट का अनिवार्य उपयोग करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, निर्धारित लेन में चलें, मोबाइल फोन का प्रयोग न करें तथा थकान या तनाव की स्थिति में वाहन चलाने से बचें।

इस अवसर पर विधायक चंद्रशेखर, जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा, एपीएमसी अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, उपायुक्त अपूर्व देवगन, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार तथा अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक का होगा कायाकल्प

शिमला/शैल। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल 'पहाड़ों की रानी' शिमला में बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं। शहर के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने लक्कड़ बाजार स्थित ऐतिहासिक आइस-स्केटिंग रिंक के व्यापक पुनर्विकास का निर्णय लिया है। वर्ष 1920 में ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित इस रिंक ने हजारों उभरते आइस स्केटर्स की प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इसे लगभग 20.22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य शिमला आने वाले पर्यटकों को बेहतर और यादगार अनुभव प्रदान करना है। साथ ही, इससे क्षेत्र में शीतकालीन खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित योजना के तहत कुछ पुरानी और अनुपयोगी अधोसंरचनाओं को हटाकर नए विकास कार्य किए जाएंगे।

शहर के मध्य स्थित इस उन्नत आइस-स्केटिंग रिंक में किए जाने वाले सुधार कार्यों से पर्यटन गतिविधियों के साथ-साथ आइस हॉकी और फिगर स्केटिंग जैसे खेलों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे खेल प्रेमियों को प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के नए अवसर प्राप्त होंगे। उभरते स्केटर्स, पेशेवर खिलाड़ियों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भविष्य में यह रिंक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी का प्रमुख मंच बनकर उभरेगा, जिससे शिमला को खेल मानचित्र पर विशेष पहचान मिलेगी।

शिक्षा मंत्री ने संस्थागत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में तेजी लाने के दिए निर्देश

योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों की समीक्षा

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए गुणात्मक शिक्षा सुधारों में तेजी लाने के निर्देश

दिए। उन्होंने राज्यभर में शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करने पर विस्तृत समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि शैक्षणिक मानकों में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में 39 छात्र एवं छात्रा विद्यालयों का विलय कर उन्हें सह-शिक्षा संस्थानों में परिवर्तित किया गया है, जबकि शून्य नामांकन वाले 39 विद्यालयों को निरस्त करने की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले विद्यार्थियों को समयवद्ध परिवहन भत्ता देने के भी निर्देश दिए गए।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि 100 से कम नामांकन वाले महाविद्यालयों का भी विलय किया जाएगा तथा शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारियों का समायोजन आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन निर्णयों से किसी कर्मचारी की सेवा प्रभावित नहीं होगी।

खेल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के तहत विभिन्न जिलों में नए व उन्नत खेल छात्रावासों को कार्यशील बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इन व्यवस्थाओं से खेल छात्रावासों में खेल विधाओं की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। साथ ही लंबित 1.2 करोड़ रुपये के डाइट फंड को शीघ्र जारी करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने एससीईआरटी मॉडयूल के आधार पर नव पदोन्नत प्रधानाचार्यो के प्रशिक्षण, रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति तथा शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 23 वर्ष समाप्त करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। बैठक में पीएम-श्री विद्यालयों की प्रगति सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

बैठक में शिक्षा सचिव, समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक, उच्च एवं स्कूल शिक्षा निदेशक सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वदेशी टीडी वैक्सीन का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई) में

देश में तैयार किए गए टेटनस और डिप्थीरिया (टीडी) के नये टीके का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को बधाई दी और इसे देश के लिए गर्व का विषय बताया।

मंत्री ने कहा कि यह टीका अब सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लगाया जाएगा। अप्रैल 2026 तक करीब 55 लाख खुराक उपलब्ध कराई जाएंगी। आगे चलकर इसकी उत्पादन क्षमता और बढ़ाई जाएगी, ताकि देशभर में जरूरत के अनुसार टीका उपलब्ध हो सके।

उन्होंने सरल शब्दों में बताया कि पहले टेटनस का अलग टीका लगाया जाता था, लेकिन अब नया टीडी टीका टेटनस के साथ-साथ डिप्थीरिया से भी सुरक्षा देगा। इससे गर्भवती महिलाओं, किशोरों और वयस्कों को दो गंभीर बीमारियों से बचाव मिलेगा। यह कदम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मजबूत करने में मदद करेगा।

मंत्री ने कहा कि भारत अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। देश में ही टीकों का निर्माण हो रहा है और भारत दुनिया के कई देशों को दवाइयां और टीके उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत ने बहुत कम समय में अपने टीके विकसित किए और करोड़ों लोगों को मुफ्त टीका लगाया।

उन्होंने यह भी बताया कि देश में हर साल करोड़ों बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त टीके लगाए जाते हैं। गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। टीकाकरण की निगरानी अब डिजिटल माध्यम से भी की जा रही है, जिससे किसी भी बच्चे या गर्भवती महिला का टीका छूट न जाये।

मंत्री ने कहा कि आज देश में टीकाकरण कवरेज लगभग 99 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इससे कई गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण पाया गया है।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे समय पर टीकाकरण करवाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। यह नया टीडी टीका देश की स्वास्थ्य सुरक्षा को और मजबूत करेगा तथा आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

युवाओं ने जानी चंद्रयान से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत की उपलब्धियां

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी, शिमला द्वारा पीएम

श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, कुनिहार में 18 और 19 फरवरी को दो दिवसीय 'विकसित भारत' चित्र प्रदर्शनी एवं जन सूचना अभियान का आयोजन किया गया।

प्रदर्शनी में विद्यार्थियों और युवाओं को चंद्रयान मिशन की सफलता से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक देश की प्रमुख उपलब्धियों से अवगत कराया गया। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता, हिमाचल प्रदेश की तीन रामसर साइट रेणुका झील, चंद्रताल झील और पोंग डैम, एम्स बिलासपुर, आईआईटी मंडी तथा राष्ट्रीय राजमार्गो सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं की जानकारी आकर्षक चित्रों के माध्यम से दी गई। केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को भी रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य कृष्ण कुमार यादव ने किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका है और ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को देश की उपलब्धियों से जोड़ते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्र सूचना कार्यालय, शिमला के सहायक निदेशक संजीव कुमार शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य युवाओं को देश की उपलब्धियों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। वरिष्ठ शिक्षक संदीप कुमार ने विषय विशेषज्ञ के रूप में विकसित भारत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। एकलव्य स्कूल, जबलपुर की प्राचार्य अविनाश रानी ने भी विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम की शुरुआत जन जागरूकता रैली से हुई, जिसमें 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लेकर 'विकसित भारत@2047' के अंतर्गत स्वच्छता और विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इसके पश्चात चित्रकला एवं नारा लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। दूसरे दिन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इस अवसर पर उप प्राचार्य अनिता कंवर, शिक्षकगण, विद्यार्थी, पीआईबी एवं केंद्रीय संचार ब्यूरो के अधिकारी-कर्मचारी तथा अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ।

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मण्डी में मध्य जलेब में शामिल हुए कुलदीप सिंह पठानिया

शिमला/शैल। अंतरराष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव मंडी-2026 के अवसर पर राज देवता माधोराय जी की अगवानी में निकाली गई मध्य जलेब में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया शामिल हुए। उन्होंने श्री राज माधो राय मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की

सुख-समृद्धि की कामना की।

मध्य जलेब के दौरान शहर श्रृद्धा, आस्था और उल्लास से सराबोर रहा। पारंपरिक वाद्ययंत्रों की ध्वनि, देव परंपराओं की झलक और श्रद्धालुओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की।

मेला मैदान पड्डल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मेले हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। मंडी की शिवरात्रि, कुल्लू का दशहरा, चंबा का मिंजर और रामपुर की लवी जैसे आयोजन प्रदेश की लोक आस्था को सशक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि महोत्सव में पहली बार शामिल होना उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव है और युवा पीढ़ी का उत्साह लोक संस्कृति के संरक्षण का सकारात्मक संकेत है।

इस अवसर पर उन्होंने मंडी नगर की स्थापना के 500वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग द्वारा तैयार विशेष कवर का अनावरण भी किया। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं।

किन्नौर में राजकीय क्रय पोर्टल पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा रैम्प कार्यक्रम के अंतर्गत क्लब सिल्क रूट बैंक्वेट हॉल, किन्नौर में राजकीय क्रय पोर्टलों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पोर्टल विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला

सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को सरकारी ऑनलाइन क्रय प्रणाली के प्रभावी उपयोग के प्रति जागरूक करना तथा उनकी क्षमता को सुदृढ़ बनाना था। इस दौरान प्रतिभागियों को सरकारी ई-बाजार मंच, केंद्रीय लोक क्रय पोर्टल तथातथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से संबंधित डिजिटल मंचों पर पंजीकरण प्रक्रिया, निविदा भागीदारी, आवश्यक औपचारिकताओं तथा विपणन विस्तार के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

जिला उद्योग केंद्र, किन्नौर के महाप्रबंधक गुरु लाल नेगी ने उद्यमियों को राजकीय क्रय पोर्टलों पर पंजीकरण कर अपने उत्पादों की दृश्यता बढ़ाने और सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम स्थानीय उद्यमों को प्रतिस्पधा बनाने और व्यवसाय विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यशाला में 68 से अधिक उद्यमियों ने भाग लिया और संवादात्मक सत्र में सक्रिय सहभागिता की। प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रक्रियाओं से संबंधित प्रश्न पूछे तथा सरकारी खरीद प्रणाली के माध्यम से नए व्यावसायिक अवसरों में रुचि दिखाई।

कार्यक्रम सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुआ। उद्योग विभाग ने एमएसएमई सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबृता दोहराई।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

केंद्र का सहयोग लेकर भी कांग्रेस सरकार केंद्र को कोस रही:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस सरकार केंद्र से भरपूर सहयोग लेने के बावजूद प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर निराधार आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि मुद्दा केवल रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) का नहीं, बल्कि राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन का है। यदि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद आरडीजी बन्द हुई है, तो वर्तमान सरकार को प्रभावी आर्थिक प्रबंधन कर स्थिति संभालनी चाहिए, न कि पूर्व सरकारों या केंद्र को दोष देना चाहिए।

उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा परंपरा का हिस्सा है, लेकिन सरकार ने इसे राजनीतिक मोड़ देने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में विरोधाभास होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन 23,000 करोड़ रूपये ऋण लेने और 26,000 करोड़ रूपये चुकाने की बात कही गई, जबकि अगले दिन अलग आंकड़े प्रस्तुत किए गए पूर्व में भी ऋण और अदायगी के अलग-अलग आंकड़े दिए गए थे, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति बनती है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि

ऋण लेना असामान्य नहीं है, परंतु तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करना उचित नहीं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगभग 40,672 करोड़ रूपये ऋण लिया गया और लगभग 38,276 करोड़ रूपये की अदायगी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आते ही वर्तमान सरकार ने 6,900 करोड़ रूपये का ऋण लेकर उसे पूर्व सरकार के खाते में दर्शाया।

वित्त आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए शासनकाल में 12वें और 13वें वित्त आयोग के दौरान हिमाचल को लगभग 18,000 करोड़ रूपये का अनुदान मिला, जबकि प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में 14वें और 15वें वित्त आयोग के दौरान लगभग 89,254 करोड़ रूपये की सहायता प्राप्त हुई, जो पांच गुना से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश को अधिक वित्तीय सहयोग वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में मिला।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं आर्थिक चुनौतियों की बात स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में संकट का राजनीतिकरण करने के बजाये ठोस नीति और वित्तीय अनुशासन अपनाना आवश्यक है। भाजपा प्रदेश हित में सहयोग के लिए तैयार है, किंतु यदि आर्थिक स्थिति का गलत चित्र प्रस्तुत कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया गया तो विपक्ष तथ्यों और आंकड़ों के साथ जवाब देगा।

विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा

है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भारत और हिमाचल प्रदेश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बजट 2026-27 में देश और देवभूमि हिमाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है।

ठाकुर ने अपने ब्यान में कहा कि बजट 2026-27 में हाइवे, रेलवे, रणनीतिक कनेक्टिविटी कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में निरन्तर निवेश का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय और कनेक्टिविटी विस्तार पर विशेष जोर से विशेषकर हिमाचल जैसे पहाड़ी और सीमावर्ती राज्यों में आर्थिक विकास को मजबूती मिल रही है तथा रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को केंद्र से कर हस्तांतरण, अनुदान सहायता और समर्पित पूंजी निवेश सहायता के माध्यम से महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थन प्राप्त हुआ है। उनके अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए हिमाचल प्रदेश को कर हस्तांतरण के तहत 13,949 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही, पिछले दशक में राज्य को कर देवोल्यूशन के माध्यम से लगभग 76,799 करोड़ रूपये तथा अनुदान सहायता के रूप में 1.41 लाख करोड़ रूपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है।

ठाकुर ने बताया कि राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उनके अनुसार, वर्ष 2020-21 से जनवरी 2026 तक हिमाचल प्रदेश को इस योजना के तहत 8,309 करोड़ रूपये से अधिक प्राप्त हुए हैं, जिससे सड़कों और अन्य विकास परियोजनाओं में निवेश संभव हुआ है।

रेलवे परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन एक महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजना है, जो हिमालयी क्षेत्र में कनेक्टिविटी को नया आयाम देगी। इसके अतिरिक्त राज्य में लगभग 255 किलोमीटर लंबाई की चार नई रेलवे ट्रैक परियोजनाएं 13,000 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश के साथ प्रगति पर हैं।

उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंब इंदौरा, बैजनाथ पपरोला, पालमपुर हिमाचल और शिमला जैसे प्रमुख स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। साथ ही अंब इंदौरा और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत सेवा की शुरुआत से यात्रियों को बेहतर और तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध हुई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार का उल्लेख करते हुए ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 2,607 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किए जा चुके हैं। भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 9,964 करोड़ रूपये की लागत से 167 किलोमीटर के रणनीतिक राजमार्ग कॉरिडोर पर कार्य जारी है। उन्होंने किरतपुर-नेरचौक खंड (NH-21) का उल्लेख करते हुए कहा कि लगभग 3,400 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित इस परियोजना से यात्रा समय में कमी आई है और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार हुआ है।

उन्होंने अटल टनल, रोहतांग का भी उल्लेख किया और इसे उच्च हिमालयी क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली ऐतिहासिक इंजीनियरिंग उपलब्धि बताया, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित हुई है और पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।

ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सृजन के लिए रिकॉर्ड संसाधन आवंटित कर रही है, किंतु कई परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण, प्रशासनिक स्वीकृतियां और समन्वय की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित विकास हिमाचल प्रदेश के आर्थिक भविष्य को सशक्त करेगा। नई रेल कॉरिडोर, आधुनिक राजमार्ग, उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डा विस्तार तथा रणनीतिक रेल परियोजनाएं राज्य को पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाने में सहायक सिद्ध होंगी।

विधानसभा में राजस्व घाटा

....पृष्ठ 1 का शेष

कार्यों में भारी खर्च हुआ, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ा। विपक्ष ने कहा कि आपदा राहत के नाम पर भी पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और विस्तृत लेखा-जोखा सदन में रखा जाये।

ऋण प्रबंधन पर भी दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष ने दावा किया कि वर्ष 2018 में 113 प्रतिशत पे-आउट रेट के साथ 7,499 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, वर्ष 2019 में 149.6 प्रतिशत, कोविड काल 2020 में 61.34 प्रतिशत, 2021 में 93.4 प्रतिशत तथा 2022 में 91 प्रतिशत पे-आउट रेट रहा। उनके अनुसार पांच वर्षों में औसत 95 प्रतिशत ऋण एवं ब्याज भुगतान किया गया, जबकि वर्तमान सरकार के तीन वर्षों में औसत पे-आउट रेट 60 प्रतिशत बताया गया। साथ ही 2012-17 के दौरान ऋण वृद्धि 66 प्रतिशत, 2017-22 में 41 प्रतिशत और 2022-24 में 140 प्रतिशत तक पहुंचने का आरोप लगाया गया।

समग्र रूप से देखा जाए तो बहस में वित्त आयोगों से प्राप्त अनुदान, टैक्स डेवोल्यूशन, केंद्रीय योजनाओं की सहायता, ऊर्जा संसाधनों का दोहन, कर्मचारियों की देनदारियां और ऋण प्रबंधन जैसे मुद्दे केंद्र में रहे।